



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 751]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 18, 2005/आषाढ 27, 1927

No. 751]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 18, 2005/ASADHA 27, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(विदेश कर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2005

आय-कर

का.आ. 1022(अ)—जबकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा सिंगापुर गणराज्य की सरकार के बीच करार को संशोधित करने वाला अनुबद्ध प्रोतोकोल उक्त प्रोतोकोल के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए करार को संशोधित करने वाले प्रोतोकोल के अनुच्छेद-7 के अन्तर्गत 1 अगस्त, 2005 को प्रवृत्त हो जाएगा ;

अतः अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा सिंगापुर गणराज्य की सरकार के बीच करार को संशोधित करने वाले उक्त प्रोतोकाल के सभी प्रावधानों को 1 अगस्त, 2005 से भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा ।

[अधिसूचना सं. 185/2005/फा. सं. 500/139/2002-वि.क.प्र.]

पूनम दत्त, संयुक्त सचिव

अनुबंध

दिनांक 24 जनवरी, 1994 को भारत में हस्ताक्षरित आय संबंधी करों के बारे में वित्तीय अपवंचन निवारण और दोहरा कराधान निराकरण के लिए भारत गणराज्य की सरकार और सिंगापुर गणराज्य की सरकार के बीच करार को संशोधित करने वाला प्रोटोकॉल

भारत गणराज्य की सरकार और सिंगापुर गणराज्य की सरकार

दिनांक 24 जनवरी, 1994 को भारत में हस्ताक्षरित आय संबंधी करों के बारे में वित्तीय अपवंचन निवारण और दोहरा कराधान निराकरण के लिए भारत के गप्ततंत्र की सरकार और सिंगापुर गणतंत्र की सरकार के बीच करार को संशोधित करने के लिए प्रोटोकॉल (एतद्पश्चात् करार के रूप में उल्लिखित) को अंतिम रूप देने की इच्छा रखते हुए,

निम्नानुसार सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद 1

करार के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 4, 5 और 6 (पूजीगत लाभ) विलुप्त कर दिए जाएंगे और निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1, 2 और 3 में उल्लिखित को छोड़कर किसी सम्पत्ति के हस्तांतरण से किसी संविदाकारी देश के निवासी द्वारा प्राप्त लाभ केवल उस देश में कर योग्य होंगे।

अनुच्छेद 2

किसी संविदाकारी देश द्वारा किए गए अनुरोध पर 'सूचना के आदान-प्रदान' (अनुच्छेद 28) से संबंधित अनुच्छेद के बारे में दूसरे संविदाकारी देश का राजस्व प्राधिकरण किसी ऐसी सूचना जो कानून के अंतर्गत उसके अपने प्रयोजनों के लिए प्राप्त करने हेतु अपेक्षित है, अपने सक्षम प्राधिकरण के जरिए प्रथम उल्लिखित संविदाकारी देश से प्राप्त करेगा और उसमें भागीदारी करेगा।

अनुच्छेद 3

1. किसी संविदाकारी देश का कोई निवासी इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 1 के लाभों के लिए हकदार नहीं होगा यदि उसके कार्यकलाप इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 1 में दिए गए लाभों का फायदा उठाने के प्राथमिक उद्देश्य से व्यवस्थित किए गए हों।

2. कोई शैल/कंड्यूट कंपनी जो किसी संविदाकारी देश का निवासी होने का दावा करती हो, इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 1 के लाभों के लिए पात्र नहीं होगी। कोई शैल/कंड्यूट कंपनी नगण्य अथवा शून्य व्यवसायिक प्रचालनों सहित अथवा उस संविदाकारी राज्य में निष्पादित निरंतर व्यवसायिक और वास्तविक कार्यकलापों सहित निवासी की परिभाषा के भीतर आने वाली कोई विधिक सत्ता है।

3. किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी कोई शैल/कंड्यूट कंपनी माना जाएगा यदि उस संविदाकारी राज्य में प्रचालनों पर उसका कुल वार्षिक खर्च¹ 200,000 सिंगापुरी डॉलर अथवा 50,00,000 भारतीय रूपए हो जो कि लाभ होने की तारीख से 24 महीने की अवधि में हुआ हो और जो संबंधित संविदाकारी राज्य में हो ।

4. किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी कोई शैल/कंड्यूट कंपनी नहीं माना जाएगा यदि

(क) वह संविदाकारी देश के मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज² में सूचीबद्ध हो, अथवा

(ख) उसका उस संविदाकारी देश में प्रचालनों पर कुल वार्षिक खर्च लाभ होने की तारीख से तुरंत पहले के 24 महीनों की अवधि में संबंधित संविदाकारी देश जैसा भी मामला हो, में 200,000 सिंगापुरी डॉलर अथवा 50,00,000 भारतीय रूपए के बराबर अथवा उससे अधिक हो ।

(स्पष्टीकरण : - सदाशयी व्यावसायिक कार्यकलाप न रखने वाली कानूनी सत्ताओं के मामले इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3.1 में शामिल होंगे ।)

अनुच्छेद 4

करार के अनुच्छेद 12 का पैराग्राफ 2 (तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज और शुल्क) विलुप्त कर दिए जाएँगे और निम्नलिखित पैराग्राफ द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :

2. तथापि, तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसी रॉयल्टीज और शुल्कों पर उस देश में कर लगाया जा सकता है जिनमें इनका प्रचालन किया गया हो और जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार होंगे, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज और शुल्कों का लाभार्थी स्वामी है तो इस प्रकार से प्रभारित कर 10% से अधिक नहीं होंगे ।

अनुच्छेद 5

यह सहमति हुई है कि दोनों संविदाकारी देशों के राजस्व प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों का एक अंतरसरकारी समूह होगा जो कम-से-कम एक वर्ष में अथवा किसी भी संविदाकारी देश के अनुरोध पर उससे पहले इस प्रोटोकॉल के प्रावधानों के कार्यकरण की समीक्षा करेगा और इस प्रोटोकॉल के प्रावधानों में सुधार सहित सुधारों की सिफारिश करेगा ।

अनुच्छेद 6

इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 1, 2, 3 और 5 तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि भारत गणराज्य की सरकार और मारीशस की सरकार के बीच दोहरे कराधान के परिवार संबंधी किसी अभिसमय अथवा करार में यह प्रावधान रहेगा कि किसी संविदाकारी देश की निवासी किसी कंपनी में शेयरों के हस्तांतरण से प्राप्तव्य कोई अभिलाभ केवल उस संविदाकारी देशों में कर योग्य होंगे जिस देश का उक्त हस्तांतरणकर्ता निवासी है ।

1. 'वार्षिक खर्च' शब्दों का अभिप्राय 12 महीने की अवधि के दौरान किए गए खर्च से है । 24 महीने की अवधि की गणना लाभ अंजित करने की तारीख से तुरंत पहले 12 महीने के दो ब्लॉकों का उल्लेख करते हुए की जाएगी ।

2. मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का अभिप्राय

(क) सिंगापुर के मामले में सिंगापुर एक्सचेंज लि., सिंगापुर एक्सचेंज सिक्योरिटीज ट्रेडिंग लि. और सेंट्रल डिपोजिटरी (पीटीई) लि. द्वारा प्रचलित सिक्योरिटी बाजार से है, और

(ख) भारत के मामले में भारत के सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी स्टॉक एक्सचेंज से है ।

अनुच्छेद 7

यह प्रोटोकोल, जो इस करार का एक अभिन्न अंग होगा, 1 अगस्त, 2005 से प्रवृत्त होगा।

जिसके साक्ष्य में अपनी-अपनी सरकारों द्वारा इस हेतु विधिवत प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली, भारत में जून, 2005 के उनतीसवें दिन को अंग्रेजी में दो प्रतियों में निष्पादित, दोनों ही पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

सिंगापुर गणराज्य की
सरकार की ओर से

कमल नाथ
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

लिम हंग कियांग
व्यापार एवं उद्योग मंत्री

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(Foreign Tax Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2005

INCOME-TAX

S.O. 1022(E).— Whereas the annexed Protocol amending the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Singapore for The Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income shall enter into force on 1st August, 2005 under Article 7 of the Protocol amending the Agreement for giving effect to the provisions of the said Protocol;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Protocol amending the Agreement between the

Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Singapore for The Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income shall be given effect to in the Union of India with effect from the 1st day of August, 2005.

[Notification No. 185/2005/F. No. 500/139/2002-FTD]

POONAM DUTT, Jt. Secy.

ANNEXURE

**PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
SIGNED IN INDIA ON 24th JANUARY 1994**

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Singapore,

Desiring to conclude a Protocol to amend the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Singapore for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income signed in India on 24th January 1994 (hereinafter referred to as "the Agreement"),

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Paragraphs 4, 5 and 6 of Article 13 (Capital Gains) of the Agreement shall be deleted and replaced by the following:

"4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of any property other than those mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall be taxable only in that State."

2156G/2005-2

ARTICLE 2

With regard to the Article on “Exchange of Information” (Article 28), on a request made by a Contracting State, the Revenue Authority of the other Contracting State shall collect, and share with the first mentioned Contracting State, through its Competent Authority, whatever information that it is competent to obtain for its own purposes under its law.

ARTICLE 3

1. A resident of a Contracting State shall not be entitled to the benefits of Article 1 of this Protocol if its affairs were arranged with the primary purpose to take advantage of the benefits in Article 1 of this Protocol.
2. A shell/conduit company that claims it is a resident of a Contracting State shall not be entitled to the benefits of Article 1 of this Protocol. A shell/conduit company is any legal entity falling within the definition of resident with negligible or nil business operations or with no real and continuous business activities carried out in that Contracting State.
3. A resident of a Contracting State is deemed to be a shell/conduit company if its total annual expenditure¹ on operations in that Contracting State is less than S\$200,000 or Indian Rs 50,00,000 in the respective Contracting State as the case may be, in the immediately preceding period of 24 months from the date the gains arise.
4. A resident of a Contracting State is deemed not to be a shell/conduit company if :
 - (a) it is listed on a recognised stock exchange² of the Contracting State; or

¹ The term “annual expenditure” means an expenditure incurred during a period of 12 months. The period of 24 months shall be calculated by referring to two blocks of 12 months immediately preceding the date when the gains arise.

² Recognised Stock Exchange refers to

a) in the case of Singapore, the securities market operated by the Singapore Exchange Limited, Singapore Exchange Securities Trading Limited and the Central Depository (Pte) Limited; and
b) in the case of India, a stock exchange recognised by the Securities and Exchange Board of India.

(b) its total annual expenditure on operations in that Contracting State is equal to or more than S\$200,000 or Indian Rs 50,00,000 in the respective Contracting State as the case may be, in the immediately preceding period of 24 months from the date the gains arise.

(Explanation: The cases of legal entities not having bonafide business activities shall be covered by Article 3.1 of this Protocol.)

ARTICLE 4

Paragraph 2 of Article 12 (Royalties and Fees for Technical Services) of the Agreement shall be deleted and replaced by the following paragraph:

“2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 10%.”

ARTICLE 5

It is agreed that there shall be an inter-governmental group consisting of representatives of the revenue authorities of the two Contracting States which shall review the working of the provisions of this Protocol at least once a year or earlier at the request of either Contracting State and may make recommendations for improvements including improvements to the provisions of this Protocol.

ARTICLE 6

Articles 1, 2, 3 and 5 of this Protocol shall remain in force so long as any Convention or Agreement for the Avoidance of Double Taxation between the Government of the Republic of India and the Government of Mauritius provides that any gains from the alienation of shares in any company which is a resident of a Contracting State shall be taxable only in the Contracting State in which the alienator is a resident.

ARTICLE 7

This Protocol, which shall form an integral part of the Agreement, shall come into force on 1 August 2005.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments have signed this Protocol.

Done at New Delhi, India, this twenty-ninth day of June 2005, in two originals in English language, each text being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDIA:

KAMAL NATH
MINISTER FOR COMMERCE AND
INDUSTRY

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF SINGAPORE:

LIM HNG KIANG
MINISTER FOR TRADE AND
INDUSTRY